[श्री चन्द्रपाल सिंह]

है कि छोटे एवं भूमिहीन किसानों को दी गई सरकारी सहायता राशि पर मूलधन पर ही अन्त तक ब्याज जोड़ा जाये और लगातार बढ़ती हुई चक्रवृद्धि ब्याज को बन्द कर दिया जाये। साथ ही ग्रामीणों से ऋण वसूलने के लिये तहसील द्वारा वसूली खर्च न लिया जाये।

(xi) Facilities and Payment of wages to canteen workers equal to those of Central Government Employees

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ भवनों में दो प्रकार के कैन्टीन चल रहे हैं। एक विभागीय और दूसरा सहकारी। गृह मंत्रालय ने दिनांक 1-10-79 को एक अधिसूचना के तहत इसे भारत सरकार के अधीन सिविल पद के धारक के रूप में घोषित किया। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों के पद संघ के कार्यों से संबंधित पदों के रूप में घोषित किये गये। इस अधिसूचना के बाद भी गृह-मंत्रालय ने केन्टीन कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित ही रखा।

स्मरणीय है कि रेल मंत्रालय ने दिनांक 22-10-1980 से ही अपने अधीन के कैन्टीन कर्मचारी को सहकारी कर्मचारी के रूप में मान लिया है और अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह ही उनका वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी रेल मंत्रालय का अनुसरण किया है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 22-4-83 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह बतलाया है कि कैन्टीन के कर्मचारियों को वे ही वेतनमान और सुविधाएं दी जायें जो केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाती हैं।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए कैन्टीन कर्मचारियों को भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि 1-10-79 से ही केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं लागू करें।

THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : Sir, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move* :

> "That the Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the African Development Bank and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Hon. Members will recall that in December, 1981, the House considered and adopted unanimously a motion in respect of India's membership in the African Development Fund. The African Development Bank is a sister organisation of the African Development Fund. Both have the same objectives; to help further the economic and social development of regional members countries by providing financial and technical assistance for selected developmental projects and programmes. The difference is in their operations, being that the African Development Fund provides loans on softer terms (lower interest rate and longer repayment period) while the African Development Bank provides loans on harder terms. The two institutions are thus modelled on the IDA and IBRD respectively.

Unlike the African Development Fund, which has as its members, non-regional countries, the initial constitution of the African Development Bank provided for membership of only regional countries. However, in order to mobilize external resources required for stimulating growth